

पुरानी पेंशन योजना को पुनः वापस लाने की बढ़ती मांग

प्रासंगिकता: जीएस-2: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन।

की-वर्ड्स: पुरानी पेंशन योजना, द्विदलीय सहमति, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, पेंशन फंड प्रबंधक, सरकारी ग्राहक, परिभाषित लाभ, परिभाषित योगदान।

चर्चा में क्यों?

- राजनीतिक दल पुरानी पेंशन योजना को पुनः शुरू करने की वकालत कर रहे हैं।
- राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस द्वारा तथा पंजाब में आम आदमी पार्टी और अब गुजरात में चल रहे चुनाव प्रचार में इन दोनों पार्टियों ने इसी तरह के वादे किए हैं।



मुख्य विचार:

- अल्पकालिक राजनीतिक विचारों से प्रेरित ऐसे प्रस्तावों से मतदाताओं के केवल एक छोटे से हिस्से को ही लाभ होता है।
- दीर्घकालिक प्रभावों की समझ के बिना, या स्थायी परिणामों की अनदेखी करने की इच्छा से प्रेरित, वे द्विदलीय सहमति के माध्यम से हासिल किए गए कठिन-जीतने वाले नीतिगत लाभों को पूर्ववत करने की धमकी देते हैं।
- इसका **सरकारी वित्त पर विनाशकारी प्रभाव** पड़ेगा।

पुरानी पेंशन योजना या परिभाषित पेंशन लाभ योजना

- यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन आय का आश्वासन देती है।
- आमतौर पर सुनिश्चित राशि अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर होती है।
- पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है।
- योजना 2004 में बंद कर दी गई थी।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

- प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2003 में पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का निर्णय लिया और एनपीएस की शुरुआत की।
- यह योजना 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार की सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में शामिल होने वाले सभी नए भर्तियों पर लागू है।
- एनपीएस की शुरुआत पर, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन किया गया।
- यह एक सहभागी योजना है, जहां कर्मचारी सरकार से मिलते-जुलते अंशदान के साथ अपने वेतन से अपने पेंशन कोष में योगदान करते हैं।
- इसके बाद निधियों को पेंशन निधि प्रबंधकों के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है।
- सेवानिवृत्ति के समय, वे कुल राशि का 60% निकाल सकते हैं, जो कर-मुक्त है और शेष 40% वार्षिकी में निवेश किया जाता है, जिस पर कर लगता है।
- इसके दो घटक हो सकते हैं - टियर I और II। टियर- II एक स्वैच्छिक बचत खाता है जो निकासी के मामले में अधिक लचीलापन प्रदान करता है, और टियर I खाते के विपरीत, कोई भी किसी भी समय निकासी कर सकता है।
- यहां तक कि निजी व्यक्ति भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
- अपनी शुरुआत के बाद से, एनपीएस ने एक मजबूत ग्राहक आधार बनाया है। अक्टूबर 2022 के अंत में, इस योजना के 23.3 लाख केंद्र सरकार के ग्राहक और 58.9 लाख राज्य सरकार के ग्राहक थे।
- इसके बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र के 15.92 लाख और असंगठित क्षेत्र के 25.45 लाख ग्राहकों सहित अन्य हैं।

पुरानी पेंशन योजना खराब अर्थशास्त्र और खराब राजनीति दोनों क्यों है?

- **परिभाषित लाभ:** पुरानी पेंशन योजना "परिभाषित लाभ" की अवधारणा पर आधारित थी।
 - इसके तहत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन अंतिम आहरित वेतन के आधार पर तय की जाती थी।
- **वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण:** हालांकि, समय के साथ इस अत्यधिक पात्रता को वित्तपोषित करना वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण होता - सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों से किए गए वादों के आधार पर निहित पेंशन ऋण की गणना ने एक गंभीर तस्वीर पेश की।
 - इस प्रकार स्थिरता और मापनीयता पर चिंताओं ने नई पेंशन योजना में बदलाव को प्रेरित किया।
- **परिभाषित योगदान:** नई पेंशन योजना "परिभाषित योगदान" की अवधारणा पर आधारित थी, जो सरकार और कर्मचारी दोनों के योगदान को तय करती थी।
- **राजनीतिक एजेंडा:** मौजूदा माहौल में, जैसा कि विपक्षी अंतरिक्ष में पार्टियां अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, वे इन कदमों को सुविधाजनक मान सकते हैं।

- **राजकोषीय निहितार्थ:** पुरानी पेंशन को पुनर्जीवित करने के वित्तीय निहितार्थ गंभीर होंगे। आरबीआई के मुताबिक, राज्यों ने 2020-21 में पेंशन के लिए 3.86 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
- यह उनके स्वयं के कर राजस्व का लगभग 26 प्रतिशत है।
 - बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए, सरकार के अपने कर राजस्व में हिस्सा और भी अधिक है।

पेंशन प्रणाली पर सरकार का नवीनतम निर्देश क्या है?

- **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)** ने हाल ही में संसद को सूचित किया कि भारत सरकार के विचाराधीन केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- **सरकार का मानना था कि पुरानी व्यवस्था को बहाल करने से सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा।**
- वित्त मंत्रालय ने पहले केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक संघ के प्रस्तावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि **"परिवर्तन आर्थिक रूप से अस्थिर होंगे।"**
- केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रिटर्न बाजार से जुड़ा होना एनपीएस की एक बुनियादी डिजाइन विशेषता है। हालांकि, **पेंशन एक दीर्घकालिक उत्पाद होने के कारण अल्पावधि अस्थिरता के बावजूद, निवेश को अच्छे रिटर्न के साथ बढ़ने में सक्षम बनाता है।**

निष्कर्ष:

- जबकि राज्यों के लिए अल्पकालिक लाभ होगा, जैसे-जैसे समय के साथ पेंशन देनदारियां बढ़ती हैं, व्यय के अधिक उत्पादक रूपों के लिए उपलब्ध धन की कम हो जाएगी।
- इन पेंशनों के वित्तपोषण का भार आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा।
- तत्काल वापसी और राहत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, राजनीतिक दलों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, और इस तरह के वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण कदमों के प्रलोभन का विरोध करना चाहिए।

स्रोत: <https://indianexpress.com/article/opinion/editorials/reviving-the-old-pension-scheme-will-turn-the-clock-back-on-hard-won-reforms-8274783/>

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

Q. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह योजना 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार की सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में शामिल होने वाले सभी नए रंगरूटों पर लागू है।
2. यह एक स्वैच्छिक, परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है।
3. यहां तक कि निजी व्यक्ति भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- a) 1 और 2 केवल
- b) 1,2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 2 और 3 केवल

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- यह योजना 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार की सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में शामिल होने वाले सभी नए रंगरूटों पर लागू है। इसलिए, कथन 1 सही है।
- यह एक स्वैच्छिक, परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है। इसलिए, कथन 2 सही है।
- यहां तक कि निजी व्यक्ति भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। इसलिए, कथन 3 सही है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्या है? पुरानी पेंशन योजना खराब अर्थशास्त्र और खराब राजनीति दोनों क्यों है? चर्चा करें।

